वर्ष: 02 अंक: 02







एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग न्यूजलेरर- जुलाई- 2022



National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110 003



वर्ष: 02 अंक: 02 जुलाई 2022

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई-मेल : singh.rr9@gmail.com 💟 @srajeshranjan

पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आगामी 15 अगस्त को देश अपनी स्वाधीनता के ७५ वर्ष पूरे करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह अंक आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह चौदहवां संस्करण है। इस संस्करण में हमने जुलाई माह के दौरान आयोग द्वारा किए गए सभी कार्यों जिसमें कई सरकारी संस्थानों में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक, राज्य कार्यालयों में मामलों की सुनवाई, मुख्यालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को शामिल किया गया है। मासिक पत्रिका का यह उद्देश्य है कि आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों पर किए जा रहे तत्काल कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपका यह सहयोग आगे भी मिलते रहे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

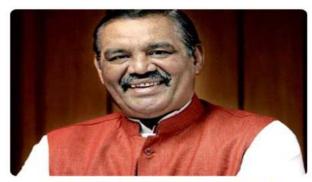
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes



CHAIRMAN



SHRI ARUN HALDER VICE CHAIRMAN



DR. ANJU BALA MEMBER



SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI MEMBER









@ncsc goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

इस स्वतंत्रता दिवस के दिन देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में यह काफी हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के प्रकाशन को भी एक साल से ज्यादा का बीत चुका है।

यह मासिक पत्रिका का चौदहवां अंक है। आजादी का अमृत महोत्सव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। इसमें सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्य योजनाओं के साथ-साथ व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों. नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया है जो हमारे विचारों को साकार करने में मदद करते हैं और सामृहिक रूप से बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करते हैं।

आयोग भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में बराबरी और भेदभाव मुक्त समाज मिल सके। इस खाई को पाटने के लिए आयोग अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए आयोग ने जुलाई माह में दौरान कई राज्यों का आधिकारिक दौरा कर संस्थानों व संभागों में अनुसचित जाति वर्ग की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं।

साथ ही आयोग को मिलने वाली शिकायतों को भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसी ही एक शिकायत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ा है। इस मामले में आयोग ने काफी सख्ती दिखाई है। ये मामला यह दर्शाने के लिए काफी है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी भी कई राज्यों में अनस्चित जाति वर्ग के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोग को तकनीकी तौर पर भी मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है ताकि देश के दुरस्थ क्षेत्रों के लोगों का सीधी पहुंच आयोग मुख्यालय तक हो सके।

अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय हिंद !

सादर धन्यवाद



SHRI VIJAY SAMPLA CHAIRMAN

विजय सांपला

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार



IDBI बैंक के कामकाज पर समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यांवयन की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक के लिए आयोग का एक दल मुंबई पहुंचा था।

इस दल की अगुवाई आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, निदेशक श्री कौशल कुमार, निदेशक (सलाहकार) श्री अजित कुमार साहू व अवर सचिव श्री किशन चंद भी मौजूद रहे।





सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आरक्षण नीति समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा द्वारा आज जुलाई माह में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेत आयोग ने समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में संबंधित एससी/एसटी संगठनों के अलावा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जुलाई माह के दौरान आयोग का एक दल बैंक की समीक्षा बैठक के लिए मुंबई पहुंचा। इस दल का नेतृत्व आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने किया। इस दल में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, निदेशक श्री कौशल कुमार, निदेशक (सलाहकार) श्री अजित कुमार साहू व अवर सचिव श्री किशन चंद भी मौजूद रहे।





आरक्षण नीति जांच के लिए SIDBI की समीक्षा बैठक



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक की अगुवाई माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री स्भाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। इससे पहले SIDBI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शिवसुब्रमण्यम रमन ने आयोग के माननीय अध्यक्ष से भेंटकर अनुसूचित जातिवर्ग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

खबरों में अयोग nia Univers



NCSC has directed the formation of a three-member committee to look into the complaints of atrocities on people from SC/ST community by World university

On July 1, National Commission for Scheduled Caste issued summons to the Vice Digest Chancellor of Jamia Millia Islamia, Professor Najma Akhtar, to appear in person before the Commission on July 19, 2022. The summons was issued by the Chairman of the Commission in a case related to caste-based atrocities and removing the constitutionally guaranteed reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in appointment and promotion by the university authority base on the complaints filed by one Harendra Kumar before the Commission. Notably notices were served by the Commission to the University earlier as well, but the University Authorities failed to comply, following which the Commission had to u

The case related to caste-based atrocities

its powers to issue summons to the VC.

In his complaint, Kumar, who belonged to Scheduled Caste, alleged that he had faced discrimination by the University authorities. Kumar was appointed as a gu computer teacher in a school run by the University. He alleged that he was illega terminated from the University from his job following a conspiracy hatched agai him by the top officials of the University. The Commission had summoned the Vi the case in 2021 as well.



Punjab moves HC against NCSC order t give quota benefit in jobs at AG office

The move comes days after the Punjab Department of Home Affairs and Justice, on May 27, NCSC stating that reservation to scheduled caste candidates is applicable while engaging var categories of law officers in the office of Advocate General.



Cricket

Trending

Lifestyle

Web Stories

Astrology

Home / Cities / Chandigarh News / National commission says 2-lakh SC stu...

Entertainment

India Vs England

CHANDIGARH NEWS

Cities

Videos

National commission says 2-lakh SC students dropped out of colleges in Punjab

Around two lakh students from the SC category dropped out of colleges between 2017 and 2020 due to non-payment of dues under a scholarship scheme by the Punjab government, the NCSC said



NCSC chairperson Vijay Sampla told reporters that the commission has sought an explanation from the Punjab government. (HT File Photo)

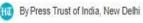
Updated on Jul 20, 2022 10:57 PM IST











Around two lakh students from the Scheduled Castes (SC) category dropped out of colleges between 2017 and 2020 in Punjab due to the nonpayment of dues under a scholarship scheme worth around ₹2,000 crore by the state government, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) said on Wednesday.

Two lakh SC students drop out of colleges in Punjab due to non-payment of dues

The data was given by the National Commission for Scheduled Caste. Its chairperson Vijay Sampla said that an explanation from the stat government has been sought



According to the National Commission for Scheduled Caste (NCSC). around two lakh students from the Scheduled Caste (SC) category dropped out of colleges in Punjab due to non-payment of dues under a scholarship scheme worth about Rs 2,000 crore by the state government. This came to light on Wednesday, July 20.

NCSC chairperson Vijay Sampla said that the Commission has sought an explanation from the state government on why the money has not been paid to colleges, despite the payment of the dues by the Central Government. He added that the Punjab government has been asked to give an explanation by next Wednesday, as per a PTI

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार रहे दीरे



unjao due to non payment of scholarshi state'

ET Online and Agencies . Last Updated: Jul 20, 2022, 07:28 PM IST

The allegations came a week after Punjab Chief Minister Bhagwant Mann ordered a probe into alleged irregularities in the post-matric scholarship scheme that had



पंजाब में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर दो लाख एससी छात्रों ने कॉलेज की



NEWS 18

surfaced during the previous Congress regime in the state. The National Commission for

> Scheduled Caste today alleged that around two lakh students f Scheduled Caste category in dropped out of colleges as t Congress-ruled state govern to pay them scholarship m getting funds from the Cen









♠ POLITICS Y GOVERNANCE Y ECONOMY DEFENCE INDIA FEATURES Y OPINION Y EVENTS Y VIDEO MORE Y

लोकासत हिन्दी

The Commission has now sought an explanation from the state gc by next Wednesday on why the money has not been paid to college the payment of dues by the Centre.

"We have taken suo motu cognisance in the matter. There have becomplaints from SC students that they are not being allowed in co government has not paid their fees. There were around three lakh who benefited from the scheme in 2017 and the number dropped t in 2020. When we asked the state government, they said these chi dropped out," NCSC chairperson Vijay Sampla was quoted as sayi.



2 lakh SC students dropped out of colleges in Punjab due to non-payment of scholarship by state: NCSC

PTI 20 July 2022 03:04 pm IST





akh students from the Scheduled Caste category dropped dues under a scholarship scheme worth around Rs 2,000

National Commission for Scheduled Caste said on



EDUCATION

nn last week ordered a comprehensive probe into alleged larship scheme that had surfaced during the previous

Summoning Sonia Gandhi to ED will raise public sympathy. BJP knows it, wants it

Zainab Sikander - 19 July, 2022

Most Popular

Why Dhankhar and Murmu are perfect fit in Modi's Mission 2024

D.K. Singh - 18 July, 2022

Is Israeli writer Yuval Harari a real scholar or a fake: Questions as experts launch new assault

Around 2 Lakh SC Students Dropped Out of Colleg Punjab Due to Non-payment of Scholarship: NCSC



post-matric scholarship scheme that had s

योजनाओं में एससी वर्ग को अधिकाधिक लाभान्वित करने

round two lakh students from the Scheduled Caste category dropped out of college due to no of dues under a scholarship scheme worth around Rs 2,000 crore by the Puniab government. Commission for Scheduled Caste said on Wednesday. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann ordered a comprehensive probe into alleged irregularities in the post-matric scholarship sch had surfaced during the previous Congress regime in the state.

NCSC chairperson Vijay Sampla told reporters that the Commission has sought an explanation from the government on why the money has not been paid to colleges despite the payment of dues by the Centr taken suo motu cognisance in the matter. There have been many complaints from SC students that the being allowed in colleges as the government has not paid their fees. "There were around three lakh SC who benefited from the scheme in 2017 and the number dropped to 1-1.25 lakh in 2020. When we aske government, they said these children dropped out," he said.



उदयपुर संभाग में समीक्षा बैठक

राजस्थान के उदयप्र संभाग में अन्स्चित जाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेत् आयोग ने समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के लिए आयोग का एक दल माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार ने की। इस समीक्षा बैठक में उदयप्र के डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, डीएम, एसपी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

SJVN प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अन्स्चित जाति आयोग के एक दल ने हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा किया। दल की अग्वाई माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। इस दौरान राजधानी शिमला में Satluj Jal Vidyut Nigam LTD. (SJVN) में अन्सूचित जाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर SJVN के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।



भरतपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी की अगुवाई में राजस्थान राज्य के भरतपुर का दौरा

किया। यहां पर आयोग ने भरतपुर जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति संगठनों एवं अधिकारियों के साथ अनुसूचित जातिवर्ग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

त्वरित कार्रवाई के निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में आये हुए व्यक्तियों की शिकायतों पर सुनवाई की।

शिकायतों को सुनने के बाद माननीय उपाध्यक्ष ने लोगों की शिकायतों को त्वरित व न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।



<u>आयोग के दल ने किया</u> <u>चंडीगढ़ का दौरा</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंज् बाला ने चंडीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न बैंको के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं एवं उनके समाधान से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श किया। साथ ही विभिन्न एससी/एसटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट कर अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा तथा समाधान हेत् विभिन्न विषयों पर चर्चा की।



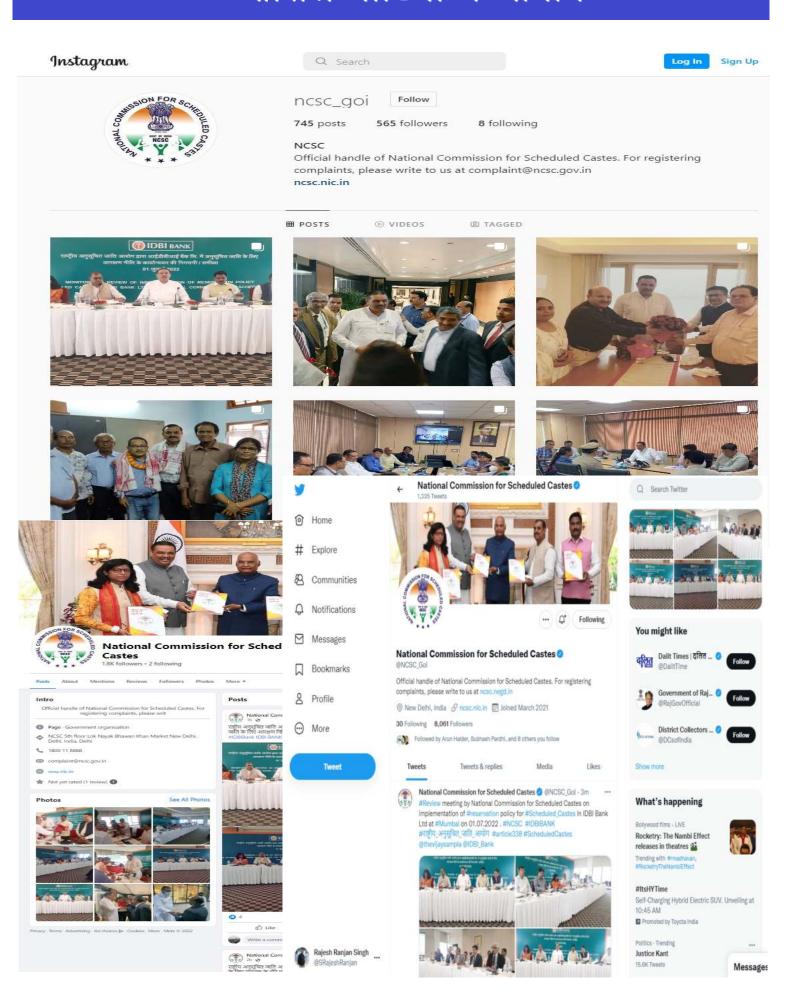
नागप्र में सुनी लोगों की समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया।

इस दौरान माननीय सदस्य महाराष्ट्र के नागपुर में अनुसूचित जातिवर्ग के व्यक्तियों से मिले।

यहां पर उन्होंने इन लोगों की शिकायतें सुनी। शिकायतों को सुनने के बाद माननीय सदस्य ने उनकी शिकायतों पर त्वरित व न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आश्वासन दिया।

सोशल मीडिया में आयोग





आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में विभिन्न जनपदों से आये हुए व्यक्तियों की शिकायतें सुनते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी।



माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी से ओएनजीसी की सीएमडी डॉ. अल्का मित्तल ने आयोग कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई।

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110 003